

प्रेषक,

डॉ. भूपिन्दर कौर औलख,

सचिव,

उत्तराखण्ड शासन।

सेवा में,

निदेशक,

अल्पसंख्यक कल्याण विभाग,

उत्तराखण्ड, देहरादून।

अल्पसंख्यक कल्याण अनुभाग

देहरादून: दिनांक: ०७ मार्च, 2017

विषय: 12वीं पंचवर्षीय योजना में एम.एस.डी.पी. योजनान्तर्गत परिव्यय में वृद्धि के फलस्वरूप प्रस्तावित निर्माण कार्यो हेतु कार्यदायी संस्था को नामित किये जाने के संबंध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक शासनादेश संख्या-568/XVII-3/16-07(34MSDP)/2014, दिनांक 21.06.2016 का सन्दर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें, जिसके माध्यम से 12वीं पंचवर्षीय योजनान्तर्गत एम. एस.डी.पी. योजना में भारत सरकार द्वारा परिव्यय में बढ़ोतरी के दृष्टिगत प्रस्तावित नए निर्माण कार्यो हेतु 'उत्तराखण्ड राज्य अवस्थापना विकास निगम लि.' को कार्यदायी संस्था नामित किया गया है।

2- इस संबंध में शासन द्वारा सम्यक् विचारोपरान्त लिये गये निर्णय के क्रम में उपरोक्त संदर्भित शासनादेश संख्या-568/XVII-3/16-07(34MSDP)/2014, दिनांक 21.06.2016 को तत्काल प्रभाव से अतिक्रमित करते हुए योजनान्तर्गत प्रस्तावित कार्यो हेतु कार्यदायी संस्थाओं को निम्नवत् नामित किया जाता है :-

1. योजनान्तर्गत भारत सरकार द्वारा अनुमोदित जनपद हरिद्वार में पेयजल योजनाओं से संबंधित 05 कार्यो, लागत ₹ 800.72 लाख हेतु 'उत्तराखण्ड पेयजल संसाधन विकास एवं निर्माण निगम'।
2. योजनान्तर्गत चिन्हित ब्लॉकों में 1000 साईकिल कार्य, लागत ₹ 30.00 लाख हेतु उत्तराखण्ड अधिप्राप्ति नियमावली-2008 यथासंशोधित-2015 के अनुसार निदेशालय स्तर पर केन्द्रीयकृत अधिप्राप्ति स्वयं करते हुए संबंधित जिला अल्पसंख्यक कल्याण अधिकारियों के माध्यम से संबंधित ब्लॉकों में नियमानुसार वितरित किये जाने की कार्यवाही की जायेगी।

3- उक्त के अतिरिक्त एम.एस.डी.पी. योजनान्तर्गत भारत सरकार द्वारा अनुमोदित समस्त कार्यो की कुल लागत ₹ 2982.68 लाख के सापेक्ष अवशेष धनराशि ₹ 2151.96 लाख के कार्यो हेतु 'उत्तर प्रदेश राजकीय निर्माण निगम' को निम्नलिखित शर्तो के अधीन कार्यदायी संस्था नामित किया जाता है :-

1. भारत सरकार के पत्र दिनांक 08.11.2016 द्वारा निर्माण कार्यो के संबंध में जारी एनेक्जर-बी में हास्टल हेतु एनेक्जर-सी में इण्टरकालेज एवं उच्चतर माध्यमिक विद्यालय हेतु दिये गये दिशा-निर्देशों का अक्षरशः अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।
2. कार्य प्रारम्भ कराने से पूर्व कार्यदायी संस्था से एम.ओ.यू. कराया जायेगा।

*ent*

3. स्वीकृत धनराशि से अधिक लागत में कार्य सम्पन्न न हो, इस हेतु विशिष्टियों पर ध्यान रखते हुए एक ऐसा आगणन गठित किया जायेगा, जिसमें पर्वतीय क्षेत्र के अनुसार विशिष्टियां निर्धारित हों एवं आगणन पुनरीक्षित न करना पड़े। विशिष्टियों का आशय फर्श, दरवाजों, विद्युत एवं अन्य मदों में आवश्यकतानुसार विशिष्टियां रखी जायें, जिससे आगणन में अनावश्यक वृद्धि न हो।
4. कार्यदायी संस्थाओं द्वारा राज्य में लागू अद्यतन अधिप्राप्ति नियमों का अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।

4- कृपया उपरोक्त निर्णय के अनुपालन में तत्काल अग्रेत्तर कार्यवाही सुनिश्चित करने का कष्ट करें।

भवदीय,

(डॉ. भूपिन्दर कौर औलख)  
सचिव।

संख्या : 303 (1)/XVII-3/2016, तददिनांकित।

प्रतिलिपि, निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-

- 1- निजी सचिव, मुख्य सचिव, उत्तराखण्ड शासन।
- 2- आयुक्त गढ़वाल/कुमायूं मण्डल, पौड़ी/नैनीताल।
- 3- जिलाधिकारी, देहरादून, हरिद्वार तथा उधमसिंहनगर।
- 4- प्रबन्ध निदेशक, उत्तराखण्ड राज्य अवस्थापना विकास निगम लि., देहरादून।
- 5- महाप्रबन्धक, उ०प्र० रा० नि० नि० लि०, ई० 34, नेहरू कालोनी देहरादून।
- 6- मुख्य अभियन्ता, उत्तराखण्ड पेयजल संसाधन विकास एवं निर्माण निगम, देहरादून।
- 7- जिला अल्पसंख्यक कल्याण अधिकारी, देहरादून, हरिद्वार तथा उधमसिंहनगर।
- ✓ 8- राष्ट्रीय सूचना केन्द्र, सचिवालय परिसर, देहरादून।
- 9- गार्ड फंजिका।

आज्ञा से,

(जी.एस. भाकुनी)  
उप सचिव।